

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 2956/2024

राधा देवी पत्नी श्री किशना राम, उम्र लगभग 36 वर्ष, बी/सी  
बिश्नोई, निवासी हनुमान नगर, कुड़ी भगतासनी जोधपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. सुवा देवी पत्नी श्री दशरथ सिंह, पत्नी प्रजापत, निवासी 151, 136, बापू  
नगर, झालामंड, जोधपुर (राजस्थान)

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री देवा राम चौधरी

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री महिपाल बिश्नोई, पी.पी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

15/07/2024

1. याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष पुलिस स्टेशन कुड़ी भगतासनी,  
जोधपुर में आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत दर्ज एफआईआर  
संख्या 153/2024, दिनांक 07.04.2024 को रद्द करने की मांग कर रहा है।
2. संक्षेप में, याचिका में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं: याचिकाकर्ता, राधा

देवी ने पी.सं.17 बी, ख.सं.950/124, गांव झालामंड के रूप में पहचानी गई एक संपत्ति प्रतिवादी संख्या 2 (शिकायतकर्ता) को 17,51,000/- रुपये में बेची, जिसका विधिवत भुगतान किया गया। चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए ऋण के कारण मूल संपत्ति के दस्तावेज बैंक के पास थे, इसलिए उसने प्रतिवादी संख्या 2 से दस्तावेजों की फोटोकॉपी का उपयोग करके संपत्ति को पंजीकृत करने के लिए कहा। ऐसा किया गया, और संपत्ति का कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 को सौंप दिया गया।

2.1 बार-बार अनुरोध के बावजूद याचिकाकर्ता ने बैंक से मूल दस्तावेज वापस लेने में देरी की। इस बीच, बैंक ने खरीदार पर बकाया ऋण चुकाने का दबाव बनाया और संपत्ति के मुख्य द्वार पर एक नोटिस चिपका दिया। यद्यपि प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को पूरी राशि का भुगतान कर दिया था, लेकिन मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

2.2 यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 को धोखा देने के इरादे से संपत्ति बेच दी और पूरा भुगतान प्राप्त करने के बाद बिक्री समझौता किया, लेकिन बैंक में राशि जमा नहीं की और मूल दस्तावेज नहीं सौंपे। इसके कारण एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने जांच शुरू की। याचिकाकर्ता का तर्क है कि आरोप निराधार और तुच्छ हैं, जिसके कारण यह याचिका दायर की गई है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने दोनों पक्षों के विद्वान वकील और विद्वान लोक अभियोजक की दलीलें सुनी हैं और केस फाइल की समीक्षा की है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता भूमि की मालिक है, क्योंकि यह पैतृक संपत्ति है, और वह कई वर्षों से अपने परिवार के साथ इस पर रह रही है। एफआईआर को झूठा और मनगढ़ंत बताया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर गलत इरादों से एक कहानी गढ़ी है,

जैसा कि एफआईआर के अवलोकन से ही स्पष्ट है। इसलिए एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।

5. इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि जांच जारी है और इसके माध्यम से सच्चाई सामने आएगी। उनका तर्क है कि इस न्यायालय के समक्ष दायर याचिका या हलफनामे में दिए गए कथनों के आधार पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता है, जिनकी अभी जांच होनी है।

6. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा लिया गया रुख उचित प्रतीत होता है।

7. विद्वान वकील के तर्कों पर विचार करने और केस फाइल और एफआईआर की सामग्री की समीक्षा करने के बाद, मैं पाता हूँ कि प्रस्तुत तर्क और आधार तथ्यात्मक दावे हैं जिनकी जांच की आवश्यकता है। ऐसी कोई कानूनी अवैधता या अनियमितता नहीं पाई गई है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो।

8. यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, एफआईआर को केवल पढ़ने पर यह दर्शाना चाहिए कि न्यायालय में आने वाले अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। यहां एफआईआर में लगाए गए आरोपों में विवादित तथ्यात्मक प्रश्न शामिल हैं, जिन पर निर्णय लिया जाना चाहिए और उन्हें स्थापित किया जाना चाहिए। मामले की योग्यता की जांच किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अनुचित होगा। इस स्तर पर एफआईआर को रद्द करना समय से पहले होगा। अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले कानून को आगे बढ़ने देना उचित है।

9. इस स्तर पर, न्यायालय की भूमिका यह निर्धारित करना है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है। वर्तमान मामले में, एफआईआर को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं करता है। जांच के माध्यम से सच्चाई सामने

आएगी, और इस प्रारंभिक चरण में एफआईआर की सत्यता पर कोई भी राय बनाना इस न्यायालय के लिए समय से पहले है। जांच, क्लोजर रिपोर्ट या मुकदमे के परिणाम के आधार पर, जैसा भी मामला हो, उचित समय पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

10. जबकि अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है, कानून और व्यवस्था के प्रवर्तन और न्याय के उचित प्रशासन में जनता के विश्वास को बनाए रखने के साथ इसे संतुलित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

11. चल रही कानूनी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्यकारी कारणों के बिना एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका उचित नहीं है। तर्कों और तथ्यों की समीक्षा करने के बाद, मेरी राय है कि यह एफआईआर को रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

12. इसलिए, हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं है, और याचिका खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता के पास जांच पूरी होने के बाद उचित चरण में उपलब्ध कानूनी उपायों की मांग करने का अधिकार है।

13. हालांकि, इस न्यायालय के हस्तक्षेप न करने को एफआईआर में आरोपों और याचिकाकर्ता के संस्करण के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। जांच एजेंसी को कानून के अनुसार अपना काम जारी रखना चाहिए, यहां की गई टिप्पणियों से अप्रभावित, जो केवल याचिका के निपटान के उद्देश्य से हैं।

14. इस याचिका में यह स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता को यहां उठाए गए तर्कों सहित अपने सभी बचाव को उचित चरण में सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, यदि और जब ऐसा होता है।

**(अरुण मोंगा), जे.**

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है )

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।